

नवभारत



अंतिम व्यक्ति तक जन लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता

जबलपुर, 1 अगस्त. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सेवा सुशासन और जनकल्याण का नया अध्याय लिख रहा है और मध्यप्रदेश सरकार उसी संकल्प को धरातल पर उतारते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है.

निःशुल्क राशन, पक्के आवास, हर घर नल से जल, शौचालय, आयुष्मान भारत योजना, स्वरोजगार और स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है. ये सारी बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को जबलपुर में घंटाघर स्थित गीता भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने 362.31 करोड़ रुपये की लागत से तैयार अमृत 1.0 सीवेज परियोजना और कैंटीन, ललपुर व तेवर में बने तीन बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया. सिविल लाइन में आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडर्न लॉन्ड्री की सौगात दी. वहीं गुरदी में 2.5 करोड़ रुपये की लागत से बने नए पक्के मत्स्य विक्रय केन्द्र का लोकार्पण किया.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जबलपुर के समग्र विकास के लिए

1 पीएम के नेतृत्व में देश लिख रहा सुशासन का नया अध्याय

2 मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर को दी कई सौगातें



मधुआरा समाज के लिए भी अवसर उपलब्ध

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल अर्थोसंरचना का विकास करना नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर में सुधार लाना है. इसी सोच के तहत रक्त सम्राज के लिए आधुनिक लॉन्ड्री परिसर और मधुआरा समाज के लिए अत्याधुनिक मत्स्य विक्रय केन्द्र विकसित किए गए हैं जिससे संबंधित समुदायों को बेहतर कार्य वातावरण, स्वच्छता और आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे.

अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने घोषणा की कि जबलपुर को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को एक वर्ष के भीतर इसका विस्तृत प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए. डॉ. यादव ने कहा कि जबलपुर स्थित मेडिकल विश्वविद्यालय को भविष्य में एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा जिससे महाकौशल क्षेत्र की विश्वस्तरीय चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी. वहीं पर्यटन

और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मदन महल क्षेत्र में आधुनिक प्राणी उद्यान ;जू एवं रेस्क्यू सेंटर विकसित किया जाएगा. इसके साथ ही जबलपुर में फर्नीचर क्लस्टर स्थापित कर स्थानीय कारीगरों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जबलपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सांदीपनि विद्यालय की स्थापना तथा अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी भूमि उपलब्ध होने पर ऐसे विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की.

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को शीघ्र शुरू कराएं : शुक्ल

नवभारत न्यूज
रीवा, 1 अगस्त. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने नगर निगम में चल रहे सीवरेज निर्माण कार्यों की समीक्षा की. उप मुख्यमंत्री ने जयंतीकुंज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के सुधार कार्य का निरीक्षण किया. मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जयंतीकुंज एसटीपी का सुधार कार्य तत्काल शुरू करें.

इस 12 एमएलडी क्षमता के प्लांट से 10 हजार से अधिक घरों से आने वाले गंदे पानी को साफ किया जायेगा. इसे चालू करने के लिए पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाये. आवश्यक



सिविल वर्क भी तत्काल शुरू कर दें. इसका निर्माण कार्य नवम्बर माह तक पूरा कराके इसे शुरू कराये. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के शुरू हो जाने से नगर की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एसटीपी के सुधार कार्य के साथ-साथ लगभग

अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

ट्रैक्टर के पलटने से घायल चालक की मौत

नवभारत न्यूज
दमोह, 1 अगस्त. पटना खुर्द के पास अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटने से सवार चालक की मौत हो गई. बताया गया कि हादसे में गंभीर चालक की स्थिति के लिए शनिवार दोपहर परिजन दमोह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे.

जहां डॉक्टर मधुर चौधरी ने चेकअप के बाद मृत घोषित कर दिया. प्राप्त जानकारी के अनुसार मुक्त बहादुर पिता रामलाल बंसल, उम्र 48 वर्ष,

निवासी पटना खुर्द थाना नोहटा बताया गया है. परिजनों में पुत्र लखन ने बताया कि पिता बहादुर ट्रैक्टर की सर्विसिंग कराने के लिए दमोह आए थे. सर्विसिंग होने के बाद जब वे ट्रैक्टर लेकर वापस घर जा रहे थे, तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारदी जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजनों ने उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी.

दो घंटे तक लिफ्ट में कैद रहे चार लोग

शुजालपुर. शुजालपुर मंडी स्थित सिविल अस्पताल में शनिवार दोपहर लिफ्ट की तकनीकी खराबी के कारण चार लोग करीब दो घंटे तक उसके भीतर फंसे रहे. घटना के बाद अस्पताल परिसर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और तकनीकी टीम की सहायता से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया, एहतियात के तौर पर लिफ्ट को पिछला बंद कर दिया गया है. ग्राम निशाना निवासी चंद्रपाल सिंह सिसोदिया बुधवार से पीड़ित पुत्री को लेकर अस्पताल पहुंचे थे.

इनका कहना है
बैठक में बताया कि खराब मशीनों को बदलने का कार्य शुरू हो गया है. सिविल वर्क 15 दिन में शुरू कर दिया जायेगा. नवंबर माह तक जयंतीकुंज एसटीपी के सुधार का कार्य पूरा हो जायेगा. सड़कों के सुधार का कार्य लगातार किया जा रहा है. घरों से सीवर लाइन में घरों से कनेक्शन तथा मुख्य सीवर लाइन से गलियों की लाइन से जोड़ने का कार्य तेजी से किया जा रहा है. बैठक में नगर निगम के कार्यालय यंत्री राजेश सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

कार्यों. चिरहुला मंदिर रोड, गोविंदगढ़ रोड तथा पीटीएस रोड में सुधार कार्य तत्काल शुरू करें.

मौलाना की कथित टिप्पणी पर कार्रवाई की उठी मांग

नवभारत न्यूज
इंदौर, 1 अगस्त. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में मौलाना की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शनिवार को चंदन नगर थाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया.

राष्ट्रीय बलाई समाज के अध्यक्ष मनोज परमार कांबड़ियों और अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी. प्रदर्शन के दौरान थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए वायरल वीडियो में की गई कथित टिप्पणी पर आपत्ति

15 करोड़ के लोन का झांसा देकर कारोबारी से डेढ़ करोड़ की ठगी

नवभारत न्यूज
इंदौर, 1 अगस्त. बड़े कारोबारियों को आसान शर्तों पर बिजनेस लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का नया मामला सामने आया है. जांच में पता चला है कि इसी नेटवर्क ने इंदौर के एक रोड कंस्ट्रक्शन कारोबारी से 15 करोड़ रुपये का लोन मंजूर कराने के नाम पर डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की राशि ले ली.

जांच में सामने आया है कि ठगों ने कारोबारी को लोन की

प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर प्रोसेसिंग फीस, एडवांस ब्याज, एनओसी और अन्य खर्चों का हवाला देकर अलग अलग समय पर रकम जमा कराई. इसके बाद भी जब लोन नहीं मिला तो कारोबारी को ठगी का अहसास हुआ. पीड़ित कारोबारी के वकील रोहित जैन ने पुलिस को बताया कि गिरोह ऐसे लोगों को निशाना बनाता था, जिन्हें बड़े लोन की जरूरत होती थी. आरोपियों ने वीडियो कॉल के

जरिए नकदी से भरे कार्टन दिखाकर कारोबारी को भरोसा दिलाया कि लोन की राशि तैयार है और कुछ औपचारिकताएं पूरी होते ही रकम जारी कर दी जाएगी. आरोप है कि गिरोह ने कुछ समय के लिए कारोबारी का मोबाइल भी अपने कब्जे में लिया और उसमें मौजूद दस्तावेज, ईमेल सहित अन्य जानकारी हासिल की. इसके बाद कुछ ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए, जिन पर कारोबारी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे.

साइबर गिरोह का नेटवर्क खंगाल रही जांच एजेंसियां

मायके में रह रही महिला को पेश करे पुलिस

नवभारत न्यूज
जबलपुर, 1 अगस्त. पति के द्वारा हाईकोर्ट में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया है कि उसकी पत्नी का मायके पक्ष वालों ने अपहरण कर लिया है. मायके पक्ष के लोग उसके बंधक बनाकर रखे हुए हैं.

हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मितल की युगलपीठ ने पुलिस को निर्देशित किया है कि वह महिला को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें. मेहर जिले के उदयपुर निवासी

रोहित कुमार चैधरी की तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया था कि उनसे मई माह में प्रेम विवाह किया था. प्रेम विवाह करने के कारण पत्नी के मायके पक्ष नाराज थे और पुलिस के माध्यम से उन्हें तथा परिजनों को प्रताड़ित करवाते थे. जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस व जिला प्रशासन को सुरक्षा प्रदान करने के संदेश में आवश्यकता अनुसार निर्णय लेने के आदेश जारी किये थे.



सीधी-सिंगरौली सड़क निर्माण को मिलेगी रफ्तार

सांसद डॉ. राजेश मिश्रा की केंद्रीय मंत्री गडकरी से भेंट बरगवां-कटनी सहित कई परियोजनाओं पर चर्चा

सिंगरौली, 1 अगस्त. क्षेत्र की लंबित सड़क परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से सीधी-सिंगरौली सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की. इस दौरान संसदीय क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने



सीधी-सिंगरौली सड़क निर्माण कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि यह मार्ग दोनों जिलों के लाखों लोगों के आवागमन का प्रमुख माध्यम है और इसके पूर्ण होने से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी. बैठक में बरगवां-कटनी

मार्ग की डीपीआर जल्द तैयार कराने का मुद्दा भी उठाया गया. सांसद ने कहा कि इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा सिंगरौली-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने पर भी चर्चा हुई.



जताई. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि वीडियो में की गई टिप्पणी से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की. मामले की सूचना मिलने पर एसपी शिवेंदु जोशी सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर उनकी शिकायत सुनी और मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद मनोज परमार ने पुलिस को

शिकायत और वीडियो को जांच जारी
एसपी शिवेंदु जोशी ने बताया कि मामले में लिखित शिकायत प्राप्त हुई है. शिकायत और वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है. जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

लिखित आवेदन सौंपा. अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता और उसमें किए गए दावों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अंकसूची की बड़ी त्रुटि सुधरी, 15 हजार विद्यार्थियों को मिली राहत

विशेष संवाददाता
भोपाल, 1 अगस्त. माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लगभग 15 हजार विद्यार्थियों की अंकसूचियों में हुई गंभीर त्रुटि को सुधारते हुए उन्हें 'ग्राइवेट/स्वाध्यायी परीक्षाधीन' के स्थान पर 'नियमित विद्यार्थी' के रूप में दर्ज कर दिया है. इस निर्णय से हजारों विद्यार्थियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है.

यह मामला मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनिकेत

द्विवेदी द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था. उन्होंने मुख्य सचिव तथा स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष इस त्रुटि को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए कहा था कि गलत वर्गीकरण के कारण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश, प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्तियों तथा रोजगार के अवसरों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. लगातार किए गए प्रतिनिधित्व के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन करते हुए प्रभावित विद्यार्थियों की

श्रेणी को नियमित विद्यार्थी के रूप में बहाल कर दिया. निर्णय का स्वागत करते हुए अनिकेत द्विवेदी ने इसे विद्यार्थियों के अधिकारों की जीत बताया. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावो व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस आगे भी विद्यार्थियों और समाज के अन्य वर्गों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी.

अवमानना एजी ने मांगी जानकारी, दो माह बाद भी विभागों ने नहीं भेजी

महालेखाकार को गंभीरता से नहीं लेते सरकारी विभाग

कन्हैया लोधी
भोपाल, 1 अगस्त. लगता है कि प्रदेश के महालेखाकार को राज्य के विभाग ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते. इसकी बानगी ये है कि एजी ने वित्तीय वर्ष 2025-25 की अवधि के विच लेखे तैयार करने के लिए विभागों ने जो जानकारी 10 जून को मांगी थी, वह जानकारी बीते 10 जुलाई तक भी नहीं भेजी गई थी, ऐसे में एजी ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिख दिया है.

पत्र मिलने के बाद वित्त विभाग ने सभी विभागों को इस मामले में नसीहत देते हुए

जानकारी भेजने की डेडलाइन भी तय कर दी है. दरअसल वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि तक की जानकारी 31 मार्च 2026 तक की स्थिति में दिया जाना है. लेकिन विभागों की ओर से वित्त लेखों की जानकारी नहीं मिलने से एजी ये जानकारी तैयार करने में लगातार देरी हो रही है. ये जानकारी देने के लिए महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर ने बाकायदा प्रारूप तैयार किया है, उसी प्रारूप में यह जानकारी देना था. ऐसे में वित्त विभाग ने सभी विभागों को जो

पत्र लिखा है उसमें साफ किया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के निर्देशों के मुताबिक जो जानकारीयां वित्त लेखे में शामिल किया जाना चाहिए, उसमें से कुछ जानकारीयां तो बजट एवं मासिक सिविल लेखाओं के रूप में मप्र सरकार से इस कार्यालय को प्राप्त हो जाती हैं. कुछ जानकारीयां अलग से मप्र शासन से अपेक्षित होंगी. इसलिए ये जानकारी एजी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है. एजी ने सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को वस्तु रूप में

बताना होगा बजट से बाहर की कितनी देनदारियां
एजी कार्यालय ने विभागों के जो प्रारूप तय किया है उसके मुताबिक विभागों को ये बताना होगा कि बजट से बाहर की कितनी देनदारियां हैं. इसी तरह शासकीय लेखा के बाहर निधियों के संचालन की जानकारी भी देना होगा. ये भी बताना होगा कि बैंक खातों में कितनी राशि जमा है. पंचायती राज संस्थाओं को दिए अनुदान की राशि का भी पूरा ब्यौरा देना होगा. इसी तरह एन्यूटी परियोजनाओं के अलावा अन्य जननिजी भागीदारी के तहत निवेश की गई राशि का भी हिसाब देना होगा. सरकार द्वारा बजट में प्रस्तावित की गई योजनाओं पर लिए गए नीतिगत निर्णयों का भविष्य के नगद प्रवाह पर प्रभाव से संबंधित जानकारी भी देना होगा.

दिए गए सहायक अनुदान की भी जानकारी विभागों से मांगी है. इसी तरह सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम, विद्युत योजनाओं के वित्तीय परिणाम, अपूर्ण कार्यों की सूची, वर्ष के

दौरान दिए गए नए ऋण और अग्रिम की जानकारी, निरंतर ऋण के रूप में स्वीकृत ऋणों के प्रकरण एवं ऋणों के बकाया पुनर्भूगतान के सारांश की जानकारी भी देना होगा.